Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

16 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. ICG और JCG ने द्विपक्षीय नौसैनिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई तट पर संयुक्त समुद्री अभ्यास 'जा माता' का आयोजन किया।

जुलाई 2025 में, भारतीय तटरक्षक बल (ICG) और जापान तटरक्षक बल (JCG) ने संयुक्त रूप से तमिलनाडु में चेन्नई तट के पास समुद्री अभ्यास 'जा माता' का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य नौसेना समन्वय, अंतर-संचालन और समुद्री क्षेत्र सहयोग को बढ़ाना था।

- **'जा माता' नामक यह अभ्यास, जो एक बोलचाल का विदाई वाक्यांश है जिसका अर्थ है "बाद में मिलते हैं", भारत और जापान के बीच आपसी संचालनात्मक समझ और समुद्री तालमेल को गहरा करने के प्रयासों के तहत आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के बीच व्यावहारिक समुद्री अभियानों, रणनीतिक यात्राओं और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का मिश्रण प्रदर्शित किया गया।**

- **इस अभ्यास में जहाज पर समन्वित गतिविधियाँ शामिल थीं, जैसे अग्निशमन अभ्यास, समुद्री डकैती-रोधी सिमुलेशन, बोर्डिंग ऑपरेशन और स्टेशन-कीपिंग। इन गतिविधियों की योजना और पर्यवेक्षण तटरक्षक क्षेत्र (पूर्व) के मुख्यालय द्वारा, पूर्वी क्षेत्र के कमांडर, महानिरीक्षक दत्तविंदर सिंह सैनी के नेतृत्व में किया गया था।**

- **यह संयुक्त अभ्यास जापान तटरक्षक बल के प्रशिक्षण पोत जेसीजी वेसल त्सुकुशिमा की छह दिवसीय समुद्री यात्रा के बाद हुआ, जो 7 जुलाई से 12 जुलाई, 2025 के बीच चेन्नई में रुका था। यह यात्रा जापान की वैश्विक महासागरीय यात्रा प्रशिक्षण पहल का एक हिस्सा थी। जेसीजी के वाइस कमांडेंट (ऑपरेशंस) वाइस एडमिरल कनौसे हिरोआकी ने इस अभ्यास के दौरान जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।**

Key Points:-

(i) बंदरगाह यात्रा के दौरान, भारतीय और जापानी तटरक्षक अधिकारियों ने कई उच्च-स्तरीय वार्ताएँ कीं, जिनमें द्विपक्षीय बैठकें, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और मानक संचालन प्रक्रियाओं एवं मिशन समन्वय पर केंद्रित संयुक्त ब्रीफिंग शामिल थीं। ये चर्चाएँ संबंधों को मज़बूत करने और आपदा प्रतिक्रिया ढाँचों तथा समुद्री कानून प्रवर्तन प्रथाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित थीं।

(ii) दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल ने महानिदेशक परमेश शिवमणि सहित भारतीय तटरक्षक बल के वरिष्ठ नेतृत्व से भी मुलाकात की, जिन्होंने नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया। बातचीत रणनीतिक ढाँचों, अंतर-संचालनीयता अभ्यासों और क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के इस्तेमाल पर केंद्रित रही।

(iii) यह आयोजन 2006 के भारत-जापान समुद्री सहयोग समझौते के तहत एक और मील का पत्थर साबित हुआ, जो भारत के सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण और हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) के अनुरूप है। जेसीजी के प्रशिक्षण पोत के अगले पड़ाव सिंगापुर के साथ, इस अभ्यास ने हिंद-प्रशांत नौसैनिक सहयोग में निरंतर गति का संकेत दिया।

2. शिवमोग्गा में शरावती पर भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल-स्टेड ब्रिज का अनावरण किया गया।

जुलाई 2025 के मध्य में, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शिवमोग्गा के सागर तालुका में शरावती बैकवाटर पर बने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल-स्टेड ब्रिज का आधिकारिक रूप से अनावरण किया। 2.44 किलोमीटर लंबा यह पुल उन्नत इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करते हुए क्षेत्रीय यात्रा, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

- **केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 14 जुलाई 2025 को उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की, उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और वरिष्ठ भाजपा नेता एवं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद थे। यह समारोह अंबरगोडलु और कलासवल्ली के बीच हुआ और इस ₹472-473 करोड़ की परियोजना के पूरा होने का प्रतीक था।**

- **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा मार्च 2019 में परियोजना को मंज़ूरी मिलने के बाद दिसंबर 2019 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा निर्मित इस पुल में एक एक्सट्राडोज़्ड बैलेंस्ड-कैंटिलीवर डिज़ाइन है, जिसमें 16 मीटर चौड़ा डेक, 11 मीटर का कैरिजवे और दोनों तरफ 1.5 मीटर के फुटपाथ हैं, और चार खंभों द्वारा समर्थित 96 केबल हैं।**

- **यह ऐतिहासिक ट्रस 2.44 किमी लंबा है और इसमें 164 पाइलों (1.8 मीटर व्यास) पर 604 बॉक्स-गर्डर खंड शामिल हैं। यह दिन के समय चलने वाली बजरा सेवा की जगह यात्रा के समय को लगभग दो घंटे कम कर देता है, जिससे मलनाड क्षेत्र के कुछ गाँवों का बेहतर संपर्क स्थापित होता है और सिगंडूर चौदेश्वरी तथा कोल्लूर मूकाम्बिका मंदिरों में जाने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधा मिलती है।**

Key Points:-

(i) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके मंत्रिमंडल द्वारा अपर्याप्त सूचना का हवाला देते हुए बैठक से दूर रहने से एक राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया। मुख्यमंत्री ने एक पत्र जारी कर बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केवल तीन दिन पहले ही उनके कार्यालय से परामर्श किया था और पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया था। गडकरी ने कहा कि औपचारिक निमंत्रण 11 जुलाई को जारी किए गए थे, जिसके बाद आभासी भागीदारी के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की गई, जिसमें सहकारी संघवाद के सम्मान पर ज़ोर दिया गया।

(ii) स्थानीय प्रभाव के अलावा, यह परियोजना एक बड़े बुनियादी ढाँचे के विकास का भी हिस्सा है—गडकरी ने ₹10,000 करोड़ के बेलगावी-हंगुंड-रायचूर चार-लेन कॉरिडोर, बेंगलुरु के रिंग रोड (₹15,000 करोड़) पर 40% प्रगति और हासन-रायचूर आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण में तेज़ी लाने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि तुमकुरु-शिवमोगा राजमार्ग का काम लगभग पूरा हो रहा है, जिससे बेंगलुरु और शिवमोगा के बीच ड्राइविंग का समय आधा हो जाएगा।

(iii) जैसे ही यह पुल जनता के लिए खुलेगा, इससे यात्रा संबंधी बाधाएँ दूर होने, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने और सिगंडूर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रखरखाव योजना के तहत, जिसमें 10 साल की प्रारंभिक अवधि और

उसके बाद द्विवार्षिक जाँच शामिल है, यह पुल कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने वाली एक टिकाऊ संपत्ति बनने के लिए तैयार है।

3. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम के सोनापुर में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया।

जुलाई 2025 के मध्य में, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने सोनापुर के बागीबाड़ी में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का आधिकारिक उद्घाटन किया। यह अभूतपूर्व सुविधा उन्नत जल-प्रौद्योगिकी समाधानों का अग्रदूत है जिसका उद्देश्य जलीय कृषि का आधुनिकीकरण, स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देना और असम के सतत विकास के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना है।

• यह समारोह 12 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया था और इसमें मत्स्य पालन मंत्री कृष्णेंदु पॉल, NABARD के मुख्य महाप्रबंधक लोकेन दास और कोलोंग-कपिली के निदेशक ज्योतिष तालुकदार सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। यह पहल गैर-सरकारी संगठन कोलोंग-कपिली, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), केंद्रीय मीठाजल जलीय कृषि संस्थान (CIFA), राज्य मत्स्य विभाग और सेल्को फाउंडेशन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है।

• एक्वा टेक पार्क में एक्वापोनिक्स, बायोफ्लोक सिस्टम, सजावटी मछली प्रजनन और आधुनिक मछली आहार उत्पादन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है, जिन्हें मत्स्यपालकों को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन क्षमताओं को लाइव प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शित किया गया, जिससे व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ और जलीय कृषकों की उत्पादकता और आय में वृद्धि हुई।

• डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने असम को एक आत्मनिर्भर ("आत्मनिर्भर") राज्य बनाने में पार्क की भूमिका पर ज़ोर दिया और मछली आयात, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से, पर निर्भरता को कम करने में मदद की। उन्होंने 2021 में अपने एक्वाकल्चर स्कूल की शुरुआत के बाद से कोलोंग-कपिली के 17 साल के प्रयासों की सराहना की—जिसने हज़ारों लोगों को मत्स्य पालन और एकीकृत कृषि प्रणालियों में प्रशिक्षित किया—और इसे युवा उद्यमिता के लिए एक उत्प्रेरक बताया।

Key Points:-

(i) असम का मत्स्य उत्पादन 2019 और 2024 के बीच दोगुना होकर 4.99 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच गया है, जिससे यह राज्य भारत का चौथा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य बन गया है। उम्मीद है कि यह पार्क पारंपरिक तरीकों को आधुनिक जलीय कृषि तकनीकों के साथ एकीकृत करके इस वृद्धि को और गति देगा।

(ii) मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और सतत आर्द्रभूमि एवं एकीकृत मत्स्य परिवर्तन (SWIFT) परियोजना जैसी केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से सहायता की घोषणा की, जिसमें ₹800 करोड़ का एडीबी-समर्थित घटक और ₹250 करोड़ की JICA-वित्त पोषित पहल शामिल है।

इसके अतिरिक्त, इस वित्तीय वर्ष में ₹8 करोड़ की लागत वाली दस मत्स्य क्लस्टर विकास परियोजनाएँ शुरू की गईं।

(iii) डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने बुनियादी ढाँचे के विस्तार की योजनाओं का भी खुलासा किया: गरुखुटी और गोलपारा में दो फ़ोर्स्ड वाटर फ़िश ब्रीड बैंक (प्रत्येक ₹5 करोड़), कछार के सिलकुरी में ₹26 करोड़ का एक आधुनिक मछली बाज़ार और सोनारीगाँव में ₹20 करोड़ का एक एकीकृत मछली अवतरण केंद्र। उन्होंने युवाओं की भागीदारी का आग्रह किया और मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान के तहत मछली पालकों को सहायता का आश्वासन दिया।

INTERNATIONAL

1. पेरिस समझौते के तहत न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर एक "राज्य" बन जाएगा।

जुलाई 2025 में, फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया के नेताओं ने पेरिस के पास ऐतिहासिक "विश्वास पर दांव" समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने न्यू कैलेडोनिया को फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर एक संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त "न्यू कैलेडोनिया राज्य" के रूप में पुनर्परिभाषित किया। इस समझौते का उद्देश्य दीर्घकालिक तनावों को स्थिर करना और अंतर्राष्ट्रीय वैधता सुनिश्चित करना है।

• यह समझौता जून के अंत में शुरू हुई दस दिनों की बातचीत के बाद सामने आया और 12 जुलाई 2025 को पेरिस के एक उपनगर, बूगीवाल में संपन्न हुआ। इस वार्ता में न्यू कैलेडोनिया के स्वतंत्रता-समर्थक और फ्रांस-समर्थक गुटों के साथ-साथ विदेशी क्षेत्र मंत्री मैनुअल वाल्स और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सहित फ्रांसीसी अधिकारी भी शामिल हुए, जिन्होंने इसे "ऐतिहासिक" और सम्मान एवं एकता की दिशा में एक आवश्यक कदम बताया।

• फ्रांसीसी संविधान के शीर्षक XIII में एक लंबित संशोधन औपचारिक रूप से "न्यू कैलेडोनिया राज्य" का दर्जा प्रदान करेगा और फ्रांसीसी नागरिकता के साथ-साथ एक विशिष्ट कैलेडोनियन राष्ट्रीयता भी लागू करेगा। यह समझौता स्थानीय संस्थाओं को विदेशी मामलों पर तत्काल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, और भविष्य में होने वाले जनमत संग्रहों से रक्षा, न्याय, मुद्रा और सुरक्षा के क्षेत्र में अधिकारों का हस्तांतरण संभव हो सकेगा।

• महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रांतीय चुनावों के लिए मतदान की पात्रता का विस्तार होगा—जिससे 1998 के बाद पैदा हुए लोगों सहित, कम से कम दस वर्षों से लगातार उस क्षेत्र में रहने वाले किसी भी निवासी को मतदान में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस चुनावी सुधार का उद्देश्य उन विभाजनों को पाटना है जिनके कारण मई 2024 में हिंसक अशांति और घातक दंगे भड़के थे, जिनमें कई जानें गईं और स्थानीय स्थिरता को नुकसान पहुँचा।

Key Points:-

(i) एक साथ दिया जाने वाला आर्थिक सुधार पैकेज न्यू कैलेडोनिया की निकल-निर्भर अर्थव्यवस्था को संबोधित करता है, जिसने अशांति के दौरान 10 प्रतिशत जीडीपी संकुचन का सामना किया था। एक रणनीतिक वित्तीय समझौते में स्थानीय रोज़गार को बढ़ावा देने और मुख्य भूमि फ्रांस पर वित्तीय निर्भरता

को कम करने के लिए बंद पड़े उत्तरी निकल प्रसंस्करण संयंत्र में परिचालन बहाल करना शामिल है।

(ii) अपने वादे के बावजूद, इस समझौते की आलोचना हुई है। कुछ कट्टरपंथी स्वतंत्रता नेताओं और नागरिक समाज समूहों का तर्क है कि इस समझौते में पूर्ण समावेशिता का अभाव है—कई स्वतंत्रता समर्थक गुटों, जिनमें हिरासत में ली गई कार्यकर्ता ब्रेंडा वानाबो-इपेज़े भी शामिल हैं, का कहना है कि यह समझौता उनके जनादेश के बिना किया गया और इसे एक अपर्याप्त समझौता बताया।

(iii) औपचारिक रूप से इसे अपनाने के लिए 2025 के अंत में फ्रांसीसी संसदीय अनुमोदन और 2026 की शुरुआत में स्थानीय जनमत संग्रह की आवश्यकता होगी। यदि इसका समर्थन किया जाता है, तो न्यू कैलेडोनिया का "मौलिक कानून" इसके संस्थानों को फिर से परिभाषित करेगा, और इसे संयुक्त राष्ट्र में एक अलग सदस्य के रूप में शामिल होने के मार्ग पर स्थापित कर सकता है - फिर भी फ्रांस के साथ संबंध तोड़े बिना।

2. दिल्ली को QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2026 में दुनिया के सबसे किफायती छात्र शहर का खिताब मिला।

दिल्ली ने हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2026 रैंकिंग में किफायतीपन के लिए विश्व स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है, जो भारतीय महानगरों की व्यापक उन्नति का एक हिस्सा है। यह महत्वपूर्ण जीत शैक्षिक सुधारों, लागत लाभ और बढ़ते नियोक्ता विश्वास को दर्शाती है।

- **QS क्वाक्वेरेली साइमंड्स द्वारा 9 जुलाई 2025 को जारी नवीनतम रैंकिंग में, दिल्ली 117वें स्थान से चढ़कर 104वें स्थान पर पहुँच गया और 96.5 के लगभग पूर्ण स्कोर के साथ वैश्विक सामर्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा। इस मूल्यांकन में रहने के खर्च, ट्यूशन के स्तर और छात्रवृत्ति तक पहुँच के मापदंड शामिल थे।**

- **मुंबई ने भारतीय शहरों में सर्वोच्च समग्र रैंकिंग हासिल की, जो 98वें स्थान पर रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 स्थानों की तीव्र छलांग है। बेंगलुरु और चेन्नई ने भी अच्छी बढ़त दर्ज की और क्रमशः 108वें और 128वें स्थान पर पहुँच गए। यह सुधार भारत के उच्च शिक्षा केंद्रों की "बढ़ती वैश्विक अपील" को दर्शाता है।**

- **दिल्ली का सबसे किफायती छात्र शहर के रूप में उभरना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) जैसे राष्ट्रीय सुधारों के अनुरूप है, जो अंतर्राष्ट्रीयकरण, गुणवत्ता और शोध-आधारित विकास पर केंद्रित हैं। क्यूएस की सीईओ जेसिका टर्नर ने कहा कि ये रैंकिंग "देश के उच्च शिक्षा परिदृश्य में एक संरचनात्मक बदलाव" का प्रतीक हैं।**

Key Points:-

(i) सामर्थ्य के अलावा, दिल्ली और मुंबई "नियोक्ता गतिविधि" संकेतक में वैश्विक शीर्ष 50 में शामिल हो गए हैं—जो स्नातकों की मज़बूत माँग को दर्शाता है। इस पैमाने पर बेंगलुरु 41 पायदान ऊपर चढ़कर 59वें स्थान पर पहुँच गया, जबकि चेन्नई 29 पायदान ऊपर आया, जो भारत के छात्र प्रतिभा पूल में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

(ii) शीर्ष स्तरीय संस्थानों की उपस्थिति भी इन परिणामों को पुष्ट करती है। दिल्ली में IIT (भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थान) दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं। मुंबई में IIT बॉम्बे और मुंबई विश्वविद्यालय हैं। बेंगलुरु और चेन्नई में IISc (भारतीय विज्ञान संस्थान), IIM (भारतीय प्रबंधन संस्थान) बैंगलोर, अन्ना विश्वविद्यालय और IIT मद्रास जैसे संस्थान मज़बूत हैं।

(iii) इस वर्ष की QS रैंकिंग, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ मेल खाती है, जहाँ रिकॉर्ड 54 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हुए, जिससे भारत विश्व स्तर पर चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया। आईआईटी दिल्ली ने संयुक्त रूप से 123वें स्थान पर रहते हुए, अब तक के सर्वोच्च प्लेसमेंट के साथ भारतीय उच्च शिक्षा में अग्रणी स्थान हासिल किया।

BANKING & FINANCE

1. UPI-PayNow सीमा-पार प्रेषण नेटवर्क का विस्तार: भारत-सिंगापुर के बीच निर्बाध लेनदेन के लिए 13 और भारतीय बैंक जुड़े।

16 जुलाई 2025 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की अंतरराष्ट्रीय इकाई NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने घोषणा की कि 13 और भारतीय बैंकों को UPI–PayNow सीमा-पार प्रेषण नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही अब इस नेटवर्क में कुल 19 बैंक भाग ले रहे हैं। यह सेवा 17 जुलाई 2025 से औपचारिक रूप से शुरू हो गई है।

- **इस कदम से अब शामिल हो चुके कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंकों के ग्राहक भारत और सिंगापुर के बीच रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। उपयोगकर्ता भारत से सिंगापुर में पैसे भेज सकते हैं और भीम, गूगल पे, फोनपे या संबंधित बैंकिंग ऐप जैसे यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके 19 भारतीय सहभागी बैंकों में से किसी में भी पैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं।**

- **यह विस्तार सितंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक अंतर-संचालनीयता पहल पर आधारित है। एशिया की पहली क्लाउड-आधारित रीयल-टाइम क्रॉस-बॉर्डर भुगतान प्रणाली के रूप में, UPI-पेनाउ ने प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और परिवारों के लिए नगण्य लागत और तात्कालिक निपटान के साथ प्रेषण को सुव्यवस्थित किया है।**

Key Points:-

(i) NIPL के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश शुक्ला ने कहा कि नेटवर्क विस्तार से द्विपक्षीय वित्तीय संपर्क मज़बूत होगा, जिससे प्लेटफ़ॉर्म अधिक समावेशी और व्यापक रूप से सुलभ होगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह विस्तार मज़बूत एन्क्रिप्शन के ज़रिए सुरक्षा को बढ़ाता है और छोटे, लगातार होने वाले धन प्रेषणों को बढ़ावा देता है जिससे सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों को लाभ होता है।

(ii) भारत से बाहर जाने वाले धन प्रेषण सात बैंकों द्वारा समर्थित हैं — जिनमें केनरा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक और भारतीय स्टेट बैंक शामिल हैं — जबकि DBS SG और लिक्विड ग्रुप के साथ बैंकिंग करने वाले सिंगापुर के उपयोगकर्ता 19 भारतीय बैंकों में से किसी में भी यूपीआई आईडी पर धन हस्तांतरण

शुरू कर सकते हैं। भारत में प्राप्तकर्ता अपने यूपीआई-लिंक्ड बैंक खातों के माध्यम से तुरंत धनराशि प्राप्त करते हैं।

(iii) UPI -PayNow लिंकेज डिजिटल वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह न केवल सीमा पार धन की आवाजाही को आसान बनाता है, बल्कि भारत के महत्वाकांक्षी 'विकसित भारत 2047' दृष्टिकोण के तहत, UPI इंटरऑपरेबिलिटी को अन्य देशों तक विस्तारित करने के लिए एक आदर्श के रूप में भी काम कर सकता है।

2. ग्रो म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला पावर सेक्टर-केंद्रित ETF और FoF लॉन्च किया।

जुलाई 2025 में, ग्रो निवेश प्लेटफ़ॉर्म की एसेट मैनेजमेंट शाखा ग्रो म्यूचुअल फंड ने भारत की पहली एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) और फंड ऑफ फंड (FoF) योजनाएं लॉन्च कीं जो पूरी तरह से पावर सेक्टर को समर्पित हैं। इन नई योजनाओं के नाम हैं 'ग्रो BSE पावर ETF' और 'ग्रो BSE पावर ETF FoF', जिनका उद्देश्य भारत में कम लागत पर पावर सेक्टर पर केंद्रित इक्विटी निवेश को बढ़ावा देना है।

• दो नई पैसिव निवेश योजनाओं का संयुक्त रूप से प्रबंधन फंड मैनेजर निखिल सातम, आकांक्षा चौहान और शशि कुमारी द्वारा किया गया है। दोनों योजनाओं के लिए न्यू फंड ऑफर (NFO) की सदस्यता 18 जुलाई 2025 को शुरू हुई थी और यह 1 अगस्त 2025 तक सक्रिय रहेगी। ये योजनाएं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के अंतर्गत पंजीकृत हैं और निवेश रिटर्न के लिए विशेष रूप से BSE पावर इंडेक्स को ट्रैक करती हैं।

• ग्रो BSE पावर ETF (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) सीधे उन कंपनियों के समूह में निवेश करता है जो BSE पावर इंडेक्स में सूचीबद्ध हैं और पावर सेक्टर से संबंधित हैं। यह योजना उन निवेशकों के लिए लक्षित है जो बिजली उत्पादन, संप्रेषण (ट्रांसमिशन) और बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्रों में इक्विटी निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि (लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन) प्राप्त करना चाहते हैं। यह स्टॉक एक्सचेंजों पर रियल-टाइम में खरीद और बिक्री की सुविधा देता है, जिससे यह पोर्टफोलियो विविधीकरण (डायवर्सिफिकेशन) के लिए उपयुक्त बनता है।

• दूसरा उत्पाद, ग्रो BSE पावर ETF FoF(फंड ऑफ फंड), एक म्यूचुअल फंड है जो ग्रो BSE पावर ETF की इकाइयों में निवेश करता है। यह उन निवेशकों के लिए आदर्श है जो सीधे शेयर बाजार में निवेश करने के बजाय म्यूचुअल फंड का रास्ता पसंद करते हैं। इस उत्पाद का उद्देश्य सीधे ETF ट्रेडिंग की परेशानी को कम करते हुए इक्विटी-इंडेक्स-आधारित रिटर्न प्रदान करना है।

Key Points:-

(i) दोनों फंड BSE पावर इंडेक्स - टोटल रिटर्न इंडेक्स (TRI) को ट्रैक करते हैं, जो भारत में बिजली उत्पादन, वितरण और बुनियादी ढाँचे से जुड़ी 14 प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है। BSE पावर इंडेक्स बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए एक लागत-प्रभावी ढाँचा प्रदान करता है, और इसमें NTPC लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा पावर और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जैसी कंपनियाँ

शामिल हैं।

(ii) इन योजनाओं में न्यूनतम निवेश राशि केवल ₹500 है और इन पर कोई एग्ज़िट लोड नहीं है, जिससे ये खुदरा निवेशकों (Retail Investors) के लिए आकर्षक बनती हैं। इन योजनाओं की शुरुआत भारत के स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) पर बढ़ते फोकस के अनुरूप है, जहां पावर सेक्टर में तेजी से बदलाव हो रहा है — बढ़ती मांग, अनुकूल सरकारी नीतियों और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy - RE) में बड़े पैमाने पर निवेश के कारण।

(iii) ग्रो म्यूचुअल फंड, जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है, की स्थापना 2011 में हुई थी और वर्तमान में इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) वरुण गुप्ता हैं। ये नई योजनाएं ग्रो द्वारा पावर सेक्टर जैसे विशिष्ट क्षेत्रों (niche segments) में लक्षित निवेश के अवसर प्रदान करने और भारत में पैसिव निवेश (Passive Investing) की पहुँच को विस्तृत करने के प्रयास का प्रतीक हैं।

ECONOMY & BUSINESS

1. साइप्रस और डेनमार्क की शिपिंग कंपनियों ने भारतीय समुद्री क्षमता बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के FDI का वादा किया।

जुलाई 2025 की शुरुआत में, साइप्रस स्थित इंटरओरिएंट नेविगेशन कंपनी लिमिटेड और डेनमार्क की डैनशिप एंड पार्टनर्स लिमिटेड ने भारत के शिपिंग क्षेत्र में ₹10,000 करोड़ के ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की घोषणा की। 2005 में इस क्षेत्र को 100% विदेशी निवेश के लिए खोले जाने के बाद से, यह भारतीय समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।

- **यह विशाल निवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 जून 2025 को साइप्रस की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के बाद हुआ है, जहाँ राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस के साथ समुद्री सहयोग एक प्रमुख एजेंडा था। यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं ने इस रणनीतिक सहयोग की नींव रखी।**

Key Points:-

(i) समझौते की शर्तों के अनुसार, इस परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित सभी जहाज भारतीय ध्वज के अंतर्गत पंजीकृत होंगे, जिससे भारत के राष्ट्रीय नौवहन टन भार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत के एक्जिम (निर्यात-आयात) माल की ढुलाई से होने वाली आय घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर ही रहेगी, जिससे आर्थिक प्रतिधारण मजबूत होगा।

(ii) इस सहयोग से भारतीय कैडेटों, प्रशिक्षुओं और नाविकों के लिए पर्याप्त रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है, साथ ही समुद्री रसद में घरेलू क्षमताएँ भी बढ़ेंगी। 1979 में स्थापित इंटरओरिएंट, दुनिया भर में 100 से ज़्यादा जहाजों का संचालन करता है, जो भारत की नौवहन क्षमता में मज़बूत विश्वास का संकेत है।

2. S&P ग्लोबल रिपोर्ट: NSE H1-CY25 में IPO फंडरेजिंग में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रहा।

जुलाई 2025 में, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने अपनी अर्ध-वार्षिक IPO लीग टेबल जारी की, जिसमें भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को कैलेंडर वर्ष 2025 की पहली छमाही (H1-CY25) के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) फंडरेज़िंग के मामले में विश्व स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त हुआ। यह रिपोर्ट भारत की पूंजी बाजार की मजबूती और वैश्विक निवेशकों के बीच NSE की भूमिका को दर्शाती है।

- **इस डेटा के अनुसार, NSE ने H1-CY25 के दौरान IPOs के माध्यम से कुल 5.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए, जो वैश्विक IPO फंडरेज़िंग पूल 61.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर का 8.9% हिस्सा है। यह प्रदर्शन भारत की वैश्विक इक्विटी पूंजी बाजारों में भागीदारी और घरेलू लिस्टिंग्स पर मजबूत निवेशक विश्वास को दर्शाता है।**

- **वैश्विक स्तर पर IPO फंडरेज़िंग में NSE से आगे तीन स्टॉक एक्सचेंज रहे—NASDAQ ग्लोबल मार्केट (12.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर), न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) (8.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर), और NASDAQ ग्लोबल सिलेक्ट मार्केट (7.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर)। NSE का चौथा स्थान भारत की प्रारंभिक बाजार गतिविधियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रदर्शित करता है।**

- **विशेष रूप से, IPO की संख्या के मामले में NSE ने सभी वैश्विक एक्सचेंजों को पीछे छोड़ दिया, और H1-CY25 में 73 IPOs की मेज़बानी की। यह संख्या NASDAQ ग्लोबल मार्केट के 66 IPOs से अधिक रही, जिससे NSE को वैश्विक स्तर पर डील वॉल्यूम के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ।**

Key Points:-

(i) रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी से पता चला है कि भारतीय शेयर बाज़ारों में पहली छमाही से लेकर वर्ष 2025 तक कुल 119 IPO जारी हुए, जिनसे कुल ₹51,150 करोड़ की राशि जुटाई गई। यह धन उगाहने की गतिविधियों में तेज़ वृद्धि दर्शाता है, जो जारीकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी और भारतीय इक्विटी में निवेशकों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

(ii) यह प्रदर्शन वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) आधार पर पूंजी जुटाने में वृद्धि को दर्शाता है, जहां H1-CY24 में 157 लिस्टिंग्स के माध्यम से ₹37,682 करोड़ जुटाए गए थे। हालांकि H1-CY25 में लिस्टिंग्स की संख्या कम रही, फिर भी कुल पूंजी में बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि इस वर्ष के IPOs का औसत आकार बड़ा रहा है।

(iii) S&P ग्लोबल द्वारा जारी यह डेटा-आधारित वैश्विक मान्यता, भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वैश्विक पूंजी बाजारों में बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है और भारत को इक्विटी बाजार निवेशकों के लिए एक मजबूत निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करती है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. सब्यसाची कॉउचर ने डिजिटल-लक्जरी रणनीति में तेजी लाने के लिए मनीष चोपड़ा को CEO नियुक्त किया।

14 जुलाई 2025 को, आदित्य बिड़ला समूह के अंतर्गत एक लक्ज़री ब्रांड, सब्यसाची कॉउचर ने मनीष चोपड़ा, जो पहले शीन इंडिया में एक वरिष्ठ नेता थे, को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। यह कदम ब्रांड की अपनी खुदरा और डिजिटल उपस्थिति को और गहरा करने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।

• मनीष चोपड़ा सब्यसाची के लिए ई-कॉमर्स और डिजिटल-फर्स्ट रणनीति का एक मज़बूत अनुभव लेकर आए हैं, और मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम), ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट इंडोनेशिया जैसी कंपनियों के साथ-साथ ज़ोवी.कॉम और लिटिलइंटरनेट जैसे उद्यमशील उपक्रमों में प्रमुख भूमिकाओं का नेतृत्व कर चुके हैं। उनके तकनीक-प्रेमी नेतृत्व से ग्राहक जुड़ाव और सर्व-चैनल एकीकरण में वृद्धि की उम्मीद है।

• उनकी सबसे हालिया भूमिका रिलायंस रिटेल के साथ एक संयुक्त उद्यम, शीन इंडिया में थी, जहाँ उन्होंने 2023 के मध्य से परिचालन की देखरेख शुरू की। सब्यसाची के साथ उस अनुभव को साझा करना, ब्रांड की चुस्त, डिजिटल-प्रथम खुदरा बिक्री की रणनीतिक दिशा को दर्शाता है—2024 में सुस्त प्रदर्शन के बाद खुद को पुनर्जीवित करते हुए।

Key Points:-

(i) सब्यसाची कॉउचर को 2021 में आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (ABFRL) ने ₹398 करोड़ में 51% हिस्सेदारी खरीदकर अधिग्रहित कर लिया था। ABFRL डिज़ाइनर और एथनिक ब्रांड्स—जैसे तरुण तहिलियानी, मसाबा, और शांतनु एंड निखिल—के साथ अपने पोर्टफोलियो को मज़बूत कर रही है, साथ ही इस साल की शुरुआत में अपनी वेस्टर्न वियर शाखा को आदित्य बिड़ला लाइफस्टाइल ब्रांड्स में अलग कर रही है।

(ii) चोपड़ा की नियुक्ति ABFRL के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है, जिसके तहत वह लग्जरी क्षेत्र में अपनी वैश्विक उपस्थिति को बढ़ावा देना चाहता है। भारतीय लग्जरी परिधान उद्योग के 2024 तक 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2033 तक 10.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, इसलिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विकास को गति देने के लिए उनका नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है।

2. वरिष्ठ IPS अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया।

जुलाई 2025 में, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने वरिष्ठ IPS अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की पहली महिला महानिदेशक (DG) के रूप में नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी। यह ऐतिहासिक नियुक्ति भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शीर्ष नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

• मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी सोनाली मिश्रा, 31 जुलाई, 2025 को निवर्तमान डीजी मनोज यादव की सेवानिवृत्ति के बाद आरपीएफ के डीजी के रूप में कार्यभार संभालेंगी। वह 31 अक्टूबर, 2026 को अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर रहेंगी। अपनी नियुक्ति के समय, वह मध्य प्रदेश पुलिस में अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) (चयन) के रूप में कार्यरत थीं।

• सोनाली मिश्रा ने कई अग्रणी और वरिष्ठ नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं, जिनमें जुलाई 2021 में पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला बनना भी शामिल है। उन्होंने कश्मीर घाटी में BSF की खुफिया शाखा का नेतृत्व करते हुए महानिरीक्षक (IG) के रूप में भी कार्य किया है, और अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में रणनीतिक पुलिसिंग का एक अनूठा रिकॉर्ड स्थापित किया है।

Key Points:-

(i) 2023 में, मिश्रा को कोलकाता, पश्चिम बंगाल स्थित सीमा सुरक्षा बल (BSF) की पूर्वी कमान का ADG नियुक्त किया गया, जिससे भारत के अर्धसैनिक बलों में सबसे अनुभवी महिला अधिकारियों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और भी मज़बूत हुई। अस्थिर और जटिल क्षेत्रों में उनके नेतृत्व के अनुभव ने RPF में उनके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(ii) उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2020 में BSF इंटेलिजेंस और कश्मीर फ्रंटियर के आईजी के रूप में कार्य करते हुए विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (PPMDS) और 2021 में पंजाब फ्रंटियर में उनके नेतृत्व के लिए सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (PMMS) शामिल हैं। ये सम्मान उनकी दीर्घकालिक सेवा उत्कृष्टता और परिचालन सफलता को दर्शाते हैं।

(iii) रेलवे सुरक्षा बल (RPF), जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, रेल मंत्रालय (MoR) के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में कार्य करता है। 1957 के RPF अधिनियम के तहत स्थापित, इसका कार्य रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा करना है। 1985 में, आरपीएफ को आधिकारिक तौर पर "संघ का सशस्त्र बल" नामित किया गया, जिससे यह भारत में परिवहन सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बल बन गया।

3. वरिष्ठ IAS अधिकारी संजय कौल को GIFT सिटी, गांधीनगर का MD और CEO नियुक्त किया गया।

जुलाई 2025 के मध्य में, गुजरात सरकार ने 2001 बैच के केरल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी संजय कौल को गांधीनगर स्थित GIFT सिटी कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया। यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। उनका कार्यकाल तीन वर्ष या अगले आदेश तक निर्धारित है।

• औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने तक, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तपन रे गिफ्ट सिटी के कार्यवाहक MD बने रहेंगे। जुलाई 2025 में केंद्र को भेजे गए एक अनुरोध के बाद, गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा नियुक्ति अधिसूचना जारी की गई।

• वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, संजय कौल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध, यूनेस्को और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, पुस्तकालय और योजनाएं, और एशियाटिक सोसाइटी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान जैसे संस्थानों जैसे विभागों की देखरेख करते हैं।

Key Points:-

(i) मूल रूप से वडोदरा, गुजरात के निवासी, कौल ने अंतर-राज्यीय प्रतिनियुक्ति के तहत गुजरात प्रशासन (2011-2016) में कार्य किया था और गुजरात पर्यटन निगम, गुजरात सूचना विज्ञान लिमिटेड, बंदरगाह, उद्योग, वित्त, गृह और ऊर्जा जैसे प्रमुख विभागों का नेतृत्व किया था। विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में उनके व्यापक प्रशासनिक अनुभव को गिफ्ट सिटी के रणनीतिक विकास को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

(ii) गिफ्ट सिटी—गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी—भारत का पहला चालू ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, जिसकी परिकल्पना सिंगापुर और दुबई जैसे वैश्विक केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए की गई है। 2015 में स्थापित और गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के तहत गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित, इस परियोजना ने 2025 तक फिनटेक और प्रतिष्ठा सूचकांकों में शीर्ष रैंकिंग सहित महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। कौल की नियुक्ति से गिफ्ट सिटी के वैश्विक परिवर्तन के अगले चरण का नेतृत्व करने की उम्मीद है।

SPORTS

1. तमिलनाडु के हरिकृष्णन ए. रा. भारत के 87वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने।

जुलाई 2025 में, चेन्नई, तमिलनाडु के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन ए. रा. ने फ्रांस के ला प्लेग्ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में अपना तीसरा और अंतिम GM नॉर्म हासिल करके प्रतिष्ठित ग्रैंडमास्टर (GM) खिताब—भारत का सर्वोच्च शतरंज खिताब—हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ, वह पिछले दो वर्षों में भारत के 87वें ग्रैंडमास्टर और तमिलनाडु के तीसरे GM बन गए हैं।

• हरिकृष्णन ए. रा. ने भारतीय ग्रैंडमास्टर डी. इनियान के खिलाफ नौवें राउंड में रणनीतिक ड्रॉ के बाद अपना तीसरा GM नॉर्म अर्जित किया, जिससे उन्हें ला प्लेग्ने टूर्नामेंट में समग्र रूप से चौथा स्थान प्राप्त करने में मदद मिली।

• इस प्रदर्शन ने फेडरेशन इंटरनेशनेल डेस एचेक्स (FIDE - अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ) के तीन GM मानदंडों और ग्रैंडमास्टर के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक 2500 अंकों की न्यूनतम एलो रेटिंग को पूरा किया।

• उनका पहला GM नॉर्म जुलाई 2023 में स्विट्जरलैंड में आयोजित बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में और दूसरा जून 2025 में स्पेन में आयोजित लिंस एंडुजार शतरंज ओपन में प्राप्त हुआ। हरिकृष्णन को इससे पहले 2018 में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर (IM) की उपाधि से सम्मानित किया गया था और उन्होंने मात्र 7 वर्ष की आयु में अपनी पहली FIDE रेटिंग प्राप्त की थी, जिससे वह

उस समय ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ियों में से एक बन गए थे। वह वर्तमान में चेन्नई स्थित शतरंज गुरुकुल अकादमी में GM आर. बी. रमेश के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

Key Points:-

(i) ग्रैंडमास्टर की उपाधि FIDE द्वारा प्रदान की जाती है, जो शतरंज की विश्व नियामक संस्था है और जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। FIDE रेटिंग मानदंडों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में पूरा किया जाना चाहिए। ला प्लेग्ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव, जहाँ हरिकृष्णन ने अपना अंतिम मानदंड हासिल किया, एक FIDE-रेटेड टूर्नामेंट है जो शीर्ष वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करता है और भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (AICF) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(ii) केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हरिकृष्णन को बधाई दी और विश्व स्तर पर भारत की बढ़ती शतरंज प्रतिभा का उल्लेख किया। उन्होंने उभरते खिलाड़ियों के समर्थन के लिए छात्रवृत्ति, अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग और विदेशी टूर्नामेंट प्रायोजन जैसे AICF के हालिया प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।

(iii) भारत अब सक्रिय ग्रैंडमास्टर्स के मामले में विश्व स्तर पर शीर्ष पांच देशों में शामिल है, जिसमें 2020 से खिताबों में वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय रूप से, विश्वनाथन आनंद 1988 में भारत के पहले ग्रैंडमास्टर बने और कोनेरू हम्पी 2002 में GM का खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थीं। हरिकृष्णन की उपलब्धि तमिलनाडु की गहरी शतरंज संस्कृति को दर्शाती है, जिसने हाल के वर्षों में कई शीर्ष भारतीय GMs का उत्पादन किया है।

AWARDS

1. राष्ट्रपति मुर्मू ने कटक में धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया।

15 जुलाई 2025 को 15वीं शताब्दी के ओडिया कवि आदिकवि सरलादास की जयंती समारोह के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहित्य और भाषा में योगदान का जश्न मनाते हुए कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रतिष्ठित कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया।

- **सरला साहित्य संसद द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम महाभारत के उड़िया संस्करण की लेखिका आदिकवि सरला दास की 600वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अपने संबोधन में, राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और भाषाई एकता पर प्रकाश डाला और कहा कि राष्ट्रीय विविधता के बावजूद, देश की एकता मज़बूत बनी हुई है - और उन्होंने अपनी भावना इस प्रकार व्यक्त की, "हमारी विविधता इंद्रधनुष के समान है।"**

- **पुरस्कार प्रदान करते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में वकालत की गई मातृभाषा शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि किसी की मूल भाषा में सीखने से सांस्कृतिक जड़ें गहरी होती हैं और अतिरिक्त भाषाओं के अधिग्रहण का समर्थन होता है।**

• कलिंग रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओड़िया भाषा और साहित्य को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि यह "न केवल मेरे लिए, बल्कि प्रत्येक ओड़िया के लिए" सम्मान की बात है, और ओड़िया भाषा के संवर्धन और वैश्वीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने का आह्वान किया।

Key Points:-

(i) राष्ट्रपति मुर्मू ने सरला सम्मान से सम्मानित बिजया नायक को ओडिया लघु कथाओं में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने दोनों सम्मानितों की उनके रचनात्मक योगदान से ओडिया साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए प्रशंसा की।

(ii) पुरस्कार समारोह महत्वपूर्ण विरासत समारोहों के साथ हुआ, जिसने भारत की साहित्यिक परंपराओं के संरक्षण में ओडिशा की भूमिका की पुष्टि की। राष्ट्रपति मुर्मू की उपस्थिति ने शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और व्यापक सांस्कृतिक नीतियों के अनुरूप क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

(iii) कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 समारोह राष्ट्रपति मुर्मू के उसी दिन रेवेनशॉ विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में भाग लेने के तुरंत बाद आयोजित किया जा रहा है, जहां उन्होंने नवाचार-संचालित शिक्षा का आह्वान किया था तथा स्नातकों के बीच "नौकरी प्रदाता" मानसिकता पर जोर दिया था।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. इजराइल ने भूस्थिर संचार उपग्रह ड्रोर-1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया।

जुलाई 2025 में, इज़राइल ने राष्ट्रीय दूरसंचार अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए अपने उन्नत अगली पीढ़ी के संचार उपग्रह ड्रोर-1 को कक्षा में प्रक्षेपित किया। इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) द्वारा इज़राइली अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से विकसित इस उपग्रह को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 दो-चरणीय रॉकेट का उपयोग करके अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से प्रक्षेपित किया गया।

• ड्रोर-1 को भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा (GTO) में स्थापित किया गया, जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। यह प्रक्षेपण स्पेसएक्स का 528वाँ समग्र मिशन और 2025 का 88वाँ प्रक्षेपण था, और साथ ही फाल्कन 9 रॉकेट की 503वीं उड़ान भी थी। यह ड्रोर-1 को इज़राइल की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाता है।

• लगभग 4.5 टन (4,500 किलोग्राम) वजन वाले ड्रोर-1 को कमर्शियल जीटीओ-1 नामक मिशन पर ले जाया गया था, जिसके पंखों का फैलाव 17.8 मीटर था और व्यापक कवरेज के लिए इसमें 2.8 मीटर लंबे एंटेना लगे थे।

• इस उपग्रह के 15 वर्षों तक संचालित होने की उम्मीद है, जो देश की दीर्घकालिक सुरक्षित संचार आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

Key Points:-

(i) ड्रोर-1 को स्वदेशी डिजिटल प्रणालियों, जियोलोकेशन तकनीकों और लचीले रीप्रोग्रामेबल पेलोड का उपयोग करके बनाया गया है, जो इसे सैन्य और नागरिक दोनों उपयोगों के लिए एक अत्यधिक उन्नत उपग्रह बनाता है। इसमें अत्याधुनिक सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किया गया है जो विदेशी तकनीकों पर निर्भरता को कम करती है। इसे अपने पूरे जीवनकाल के दौरान पृथ्वी से रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है।

(ii) 2018 से इस मिशन में अनुमानित 200 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया गया है, जिससे यह इज़राइल की सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष संचार परियोजनाओं में से एक बन गई है।

(iii) ड्रोर-1 कम से कम 2040 तक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करेगा, तथा रक्षा और सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षित, उच्च क्षमता वाले डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम करेगा।

2. चीन ने कीटों को नियंत्रित करने के लिए विश्व का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रक 'साइबॉर्ग बी' विकसित किया है।

जुलाई 2025 में, चीन के बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT) के प्रोफेसर झाओ जियेलियांग के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क-नियंत्रण उपकरण 'साइबॉर्ग बी' विकसित किया है, जिसका वजन मात्र 74 मिलीग्राम (mg) है। यह उपकरण मधुमक्खियों की उड़ान को सीधे नियंत्रित कर सकता है और माइक्रो-रोबोटिक्स तथा निगरानी क्षेत्र में नई संभावनाओं को जन्म देता है।

- **'साइबॉर्ग बी' को मधुमक्खी की पीठ पर लगाया जाता है और यह तीन सूक्ष्म सुइयों के माध्यम से सीधे उसके मस्तिष्क से जुड़ता है। यह उपकरण विद्युत संकेत भेजता है, जिससे कृत्रिम संवेदी अनुभूतियाँ उत्पन्न होती हैं और मधुमक्खी को मोड़ने, आगे बढ़ाने या पीछे ले जाने जैसे निर्देश दिए जा सकते हैं।**

- **इस खोज को चीनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जर्नल में प्रकाशित किया गया है, जहाँ इसे नौ अलग-अलग पल्स पैटर्न पर सफलतापूर्वक परखा गया। इन संकेतों को मधुमक्खियों और तिलचट्टों की गतिविधियों से जोड़ा गया और प्रयोगशाला में उनकी प्रतिक्रियाएं एक समान पाई गईं।**

- **प्रयोगों के दौरान देखा गया कि डिवाइस से लैस मधुमक्खियाँ हवा में उड़ान के दौरान निर्देशों का पालन करती थीं, जबकि तिलचट्टे तय किए गए मार्ग पर चलते थे और रास्ते से बहुत कम विचलन होता था, जिससे तकनीक की विश्वसनीयता प्रमाणित हुई।**

Key Points:-

(i) यह तकनीक आपदा बचाव कार्यों, पर्यावरण निगरानी, जासूसी अभियानों, और संवेदनशील क्षेत्रों में निरीक्षण जैसे कार्यों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, विशेषकर वहाँ जहाँ ड्रोन आकार में बड़े या अधिक शोर करने वाले होते हैं।

(ii) अनुसंधानकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि यह डिवाइस अत्यधिक हल्का (74 मिलीग्राम) है, जिससे यह मधुमक्खियों की प्राकृतिक उड़ान में कोई बाधा नहीं डालता — यह पिछली तकनीकों की तुलना में एक बड़ी प्रगति है।

(iii) यह खोज न्यूरो-नियंत्रित बायोहाइब्रिड रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जहाँ जीवित जीवों को तकनीकी उद्देश्यों के लिए वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे पारंपरिक मशीनों के मुकाबले एक ऊर्जा-कुशल, शांत और संकीर्ण स्थानों में कार्य करने वाला विकल्प मिल सकता है।

OBITUARY

1. नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

13 जुलाई, 2025 को नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी का 82 वर्ष की आयु में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में निधन हो गया। एक प्रमुख सैन्य और राजनीतिक हस्ती, बुहारी ने 2015 से 2023 तक लगातार दो कार्यकालों तक नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और अपने पीछे आर्थिक सुधारों और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों की विरासत छोड़ गए।

• मुहम्मदु बुहारी का जन्म 17 दिसंबर, 1942 को नाइजीरिया के कटसिना राज्य के दौरा में हुआ था। उन्होंने शुरुआत में सेना के माध्यम से सार्वजनिक सेवा में प्रवेश किया, 1961 में नाइजीरियाई सेना में शामिल हुए और कई अंतरराष्ट्रीय अकादमियों में अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त किया।

• उनके प्रारंभिक सैन्य अनुभव ने उन्हें नाइजीरिया के विकसित होते उत्तर-औपनिवेशिक रक्षा और शासन संरचनाओं में प्रमुख व्यक्तियों में से एक के रूप में स्थापित किया।

• 1975 में जनरल याकूब गोवन को अपदस्थ करने वाले तख्तापलट के बाद वे पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। दिसंबर 1983 में एक सैन्य तख्तापलट के ज़रिए बुहारी खुद तत्कालीन राष्ट्रपति शेहु शगारी को हटाकर राष्ट्राध्यक्ष बने। अपने सैन्य कार्यकाल (1983-1985) के दौरान, उन्होंने कठोर आर्थिक अनुशासन लागू किया और नागरिक उत्तरदायित्व को बहाल करने, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए अपना बहुचर्चित "अनुशासनहीनता के विरुद्ध युद्ध" अभियान चलाया।

Key Points:-

(i) लोकतांत्रिक राजनीति में वापसी करते हुए, मुहम्मदु बुहारी ऑल प्रोग्रेसिव्स कांग्रेस (APC) के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने और 2015 में गुडलक जोनाथन को हराकर निर्वाचित हुए। नाइजीरिया के इतिहास में यह पहली बार था कि किसी मौजूदा राष्ट्रपति को लोकतांत्रिक चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। बुहारी 2019 में फिर से निर्वाचित हुए और मई 2023 तक पूरे दो कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर रहे।

(ii) राष्ट्रपति के रूप में, बुहारी ने वित्तीय अनुशासन, भ्रष्टाचार-विरोधी और सुरक्षा स्थिरता पर केंद्रित प्रमुख आर्थिक नीतियों को लागू किया, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में आतंकवाद के जवाब में। उनके प्रशासन ने सामाजिक निवेश कार्यक्रम, कृषि पुनरुद्धार योजनाएँ और तेल निर्यात पर निर्भरता कम करने के उपाय शुरू किए। उन्होंने अफ्रीकी संघ (AU) और ECOWAS (पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय) के भीतर क्षेत्रीय कूटनीति पर भी ज़ोर दिया।

(iii) नाइजीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति असिवाजू बोला अहमद अडेकुनले टीनुबू हैं, जो 2023 में बुहारी के उत्तराधिकारी बनेंगे। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा

है और राष्ट्रीय मुद्रा नाइजीरियाई नाइरा (NGN) है। बुहारी के निधन से नाइजीरियाई नागरिक और सैन्य नेतृत्व में एक लंबे अध्याय का अंत हो गया है और पूरे अफ्रीका और दुनिया भर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है।

Static GK

New Caledonia	राजधानी: नौमिया	मुद्रा: सीएफपी फ्रैंक
Cypriot	राजधानी: निकोसिया	मुद्रा: यूरो
National Stock Exchange of India Limited	MD और CEO : आशीषकुमार चौहान	मुख्यालय: मुंबई
Israel	प्रधानमंत्री: बेंजामिन नेतन्याहू	राजधानी: यरुशलम
Nigeria	राष्ट्रपति : असिवाजु बोला अहमद अडेकुनले टीनुबू	राजधानी : अबुजा
China	राष्ट्रपति: शी जिनपिंग आधिकारिक	भाषाएँ: मंदारिन, पुतोंगहुआ
Indian Coast Guard (ICG)	महानिदेशक (DG) : परमेश शिवमणि	मुख्यालय: नई दिल्ली
Karnataka	मुख्यमंत्री: सिद्धारमैया	राज्यपाल: थावर चंद गहलोत
Assam	मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा	राज्यपाल: लक्ष्मण आचार्य
Groww Mutual Fund	CEO : वरुण गुप्ता	मुख्यालय: मुंबई
GIFT City Company Limited	मुख्यालय : गांधीनगर, गुजरात	स्थापना : 2015